

सं०स०-11/आ०प्र०(विविध)-01/2024-348(11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक- 30/04/2025

विषय:- वर्ष-2025 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

प्रसंग:- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1292/आ०प्र०, / दिनांक-09.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य में हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य के बाढ़ प्रवण जिलों में 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते हैं साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होती हैं। इन अति बाढ़ प्रवण जिलों एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से जान-माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती हैं। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाये जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु बाढ़ प्रवण जिलों के साथ-साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं :-

(क) सामान्य:-

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोक-थाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/ आरक्षी अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ आपूर्ति विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल-जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :-

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी सगठनों के साथ Mock Exercise/ Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

(ग) निरोधात्मक :-

शुद्ध पेयजल आपूर्ति:-

1. ऐसे सभी पेयजल स्रोतों की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई-जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधारण व्यवहार में लाते हों। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/ कर्मियों की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
2. पेयजल स्रोत बाढ़ के पानी/जल-जमाव से प्रभावित होते हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे स्रोतों के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े स्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।
3. विगत वर्षों के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल-जमाव की स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से डेंगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।
4. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेंगे तथा उसकी जाँच संक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करावेंगे।
5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत “पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया” में वर्णित निर्देशों का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेबसाइट-www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) चिकित्सा दलों का गठन :-

1. जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों रहेंगे जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजे जायेंगे।
2. बाढ़ के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में जल-जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार/पंचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मियों/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेंगे एवं महामारी नियंत्रण करेंगे।

(च) दवाओं की उपलब्धता :-

1. विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एव एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ले इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एव ए0आर0भी0 (ARV) का भंडारण सुनिश्चित कर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल हैं। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अध्याचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करें। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
3. बाढ़ के समय/बाढ़ के पश्चात कुत्ता एव सियार काटने की घटनाएँ होती रहती हैं। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) उपचारात्मक:-

1. सर्पदंश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल-जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से सॉप बाहर आ जाते हैं जिससे सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, इसलिए सुनिश्चित कर ले कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदंश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेंगे।
2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे एव गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एव इसके लिए डिलिवरी कीट एवं मैटरनिटी हट की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेंगे।
3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध में भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) अस्थायी अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्था:-

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और प्रभावितों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0 उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेंगे जबतक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे।

Amid

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/कस्बा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नौका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका औषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेगे।

(झ) प्रशासनिक व्यवस्था:-

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के सबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटा कर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे जबतक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक-थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होने तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।
5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायेगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्भेदन के स्थिति में आवश्यक कार्यवाई करेंगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगे।
6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण:-

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।
2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषाग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषाग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।
3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की संख्या/ कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/ स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई-मेल/फैक्स से ससूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ सलग्न प्रपत्र फार्म-‘ए’, फार्म-‘बी’ एवं-फार्म ‘सी’ में वर्णित विवरणों के अनुसार सकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषाग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई-मेल ssosbihar@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस सदर्थ में सम्बंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षापरांत आकलन करावेंगे कि भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन सम्बंधित कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत “बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया” में वर्णित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :-

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के टौल फ्री दूरभाष संख्या-‘104’ से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई-मेल आईडी ssobihar@gmail.com पर सूचना भेजी जा सकती है।
2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलों से महामारी के समय में प्रभावितों/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषाग को अद्यतन स्थिति से अवगत करावेंगे। इस कोषाग का दायित्व होगा कि

Amal

प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

- 3 निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेगे, जो बाढ़ से उत्पन्न महामारी के रोक-थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापाक-11/आ०प्र०(विविध)-01/2024-348. (11)/स्वा०, पटना, दिनांक-30.04.2025

प्रतिलिपि:- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (RMRIMS) अगमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य /अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित कोई-मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापाक-348(11) पटना, दिनांक : 30.04.2025

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

0537 (श्री 15/4/25)

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना-800023

दूरभाष. 0612 2294201, 2294202 (फैक्स), ई मेल. secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक-02/आ0आ0(बाढ़)-07/2025/1292/आ0प्र0,

पटना-23 दिनांक-09-04-25

प्रेषक

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पशु एवं मत्स्य ससाधन विभाग/

गृह विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/

कृषि विभाग/परिवहन विभाग/पंचायती राज्य विभाग/

नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:- संभावित बाढ़, 2025 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः प्रत्येक वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राज्य में 29 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिला की श्रेणी में आते हैं। कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं, जो बाढ़ प्रवण जिला के रूप में चिन्हित नहीं हैं। इन जिलों में बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदियों यथा-पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी के जलस्तर का बढ़ जाना है। अतएव बाढ़ प्रवण जिले के साथ-साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ पूर्व तैयारी किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से लोगों को ससमय राहत पहुँचाया जा सके एवं होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

अतएव अनुरोध है कि संभावित बाढ़, 2025 को देखते हुए बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुरूप अपने विभाग से संबंधित पूर्व तैयारियाँ कर ली जाय।

विश्वासभाजन,

अपर मुख्य सचिव